[श्री नरेश अग्रवाल]

लीजिए, इराक में आई.एस.आई.एस. नाम का एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ, जिसने इराक को तबाह कर दिया और सीरिया को तबाह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है, लेकिन हमारा देश आज भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसको राजनीतिक का मुद्दा न बनाया जाए। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, झारखंड में किसकी सरकार है या आन्ध्र प्रदेश में किसकी सरकार है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का समाधान हो। पंजाब में आतंकवाद आया था, उस समय भी कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इच्छाशक्ति की कमी है। पंजाब से आतंकवाद जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया गया। हमारी सेना कमजोर नहीं है, चाहे बाहरी आतंकवाद हो, चाहे घरेलू आतंकवाद हो, हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स कमजोर नहीं है, लेकिन इसमें सरकार की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... छत्तीसगढ़ में आतंकवादी घटना होने के बाद मैंने सोचा था कि सरकार आतंकवाद की समस्या का समाधान करेगी। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस आतंकवाद को, चाहे घरेलू हो या बाहरी, समाप्त करने के लिए एक रणनीति बनाएं, ठोस रणनीति बनाएं और इसको समाप्त करने का काम करें। धन्यवाद।

Concern over increase of bad bank loans under litigation by 10 per cent

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर समस्या की तरफ पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... महोदय, देश में विगत दिनों में तीन लाख किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उसका बड़ा कारण यह है कि कर्जा वसूली में उनकी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बैल, गहने और मकान की नीलामी होती है, उस शर्म की वजह से वे आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर 53 हजार करोड़ रुपए देश के बड़े पूंजीपतियों के ऊपर बकाया हैं और 406 डिफॉल्टर्स हैं, जिन पर 70,300 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन आज तक न किसी के नाम घोषित किए गए, न किसी डिफॉल्टर को नोटिस दिया गया, न उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया, न कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुईं। इस समय जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, सात वर्षों में इसके 4.95 लाख करोड़ रुपए उनके ऊपर बकाया हैं। यह बकाया बैंक्स और financial institutions के हैं। सर, 36 महीने में गोल्ड, डायमंड और ज्वैलरी पर ड्यूटी माफ करने के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय एक और नई बहस चल रही है और चूंकि इसमें बहुत सारे माइंडसेट एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए बहस नहीं होती है। अभी Morgan Stanley के चेयरमैन हैं मि.पी.जे. नायक। पिछली सरकार में उनकी अध्यक्षता में बैंकों की efficiency के लिए एक कमेटी बनाई गई। यह वैसा ही है, जैसे बगुलों में मछलियों के कल्याण की सलाह ली जा रही हो। इसमें यह है कि अमेरिका में पिछले पांच-छः वर्षों में 480 बैंक दिवालिए घोषित हो गए, पिछले साल 24 और इस साल 17 बड़े बैंक दिवालिए घोषित हो गए और अमेरिकनपरस्त जो ब्यूरोक्रेसी इस देश में है, वित्त मंत्रालय में जो ऑफिसर बैठे हैं, वे रिटायर होते हैं और इन कमेटियों के चेयरमैन बन जाते हैं। Mr. Naik is one of them. अब उसने सुझाव दिए हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय 2.14 लाख रुपए की शेयर पूंजी बैंकों में लाना चाहते हैं और यह एक * है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, हम भी उस घटनाक्रम में उसके साथ थे, जब बैकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो देश में एक नई आशा जगी थी। आज उसकी 50वीं वर्षगांठ है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, your time is over. ...*(Interruptions)...*

श्री के.सी. त्यागी : पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ-साथ जो बैंक्स हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : ठीक है, आपका टाइम अब खत्म हो गया है।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री शरद यादव (बिहार) : सर, मैं इस विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I too associate myself with the issue.

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : सर, अगर एक गरीब आदमी जब बिजली का बिल पे नहीं कर पाता तो उसकी बिजली काट दी जाती है। जब कोई कार का लोन नहीं चुकाता है, तो उसे बाउंसर्स उठाने के लिए आ जाते हैं, किन्तु यहां पर जो नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स हैं, वे छः लाख करोड़ से ज्यादा की हैं। मेरा यह कहना है कि इनकी वसूली की जानी चाहिए, इन लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और इनके ऊपर लगातार बैंकों का कर्जा है। ...(**व्यवधान**)... ये अपना रुपया चुका नहीं रहे, किन्तु आई.पी.एल. की टीमें खरीदनें के लिए इनके पास पैसा है। ...(**व्यवधान**)... एक कम्पनी इनको पैसा देती है नहीं, परन्तु दूसरी कम्पनियां इनको ...(**व्यवधान**)... मैं इनके साथ स्वयं को एसोसिएट करता हूं।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated) : Sir, I too associate myself with the issue.

श्री के.सी. त्यागी : सर, मैं आठ लोगों के नाम लेना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हो गया It is not going on record. तीन मिनट के बाद रिकार्ड में नहीं आएगा, बैठिए।

श्री के.सी. त्यागी : **

श्री उपसभापति : बोलने का कोई फायदा नहीं है, यह रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, बैठिए।...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इसमें तीन मिनट के बाद रिकॉर्ड में नहीं आएगा, यह इधर का रूल है। ...(**व्यवधान**)... यह हाउस का रूल है, आपको नहीं मालूम?

---

*Expunged as ordered by the Chair.

**Not recorded.

श्री के.सी. त्यागी : *

श्री उपसभापति : नाराज होने से क्या फायदा है? आप मेरे दोस्त हैं, नाराज मत होइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागी : *

Issue concerning teachers, students and employees of Allahabad University

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अब इसका नाम दूर तक नजर नहीं आता है। हालत यह है कि शिक्षक, कर्मचारी और छात्र सभी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुखर हैं। आज इनका धरना एवं प्रदर्शन चल रहा है। संघटक महाविद्यालयों के प्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की विभेदकारी, उपेक्षापूर्ण और अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण महाविद्यालयों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर किसी न किसी बहाने विगत लगभग 9 वर्षों से 11 संघटक महाविद्यालयों के 110 शिक्षकों की पदोन्नति और नये शिक्षकों की भर्ती रोके हुए है और इससे भी दुखद बात यह है कि सभी शिक्षकों की अब दो-दो पदोन्नतियां बाकी हैं। शिक्षकों के लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। अनेक विभाग बिना शिक्षकों के हैं और उनसे कहीं अधिक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की सीटें सीमित हैं, फिर भी संघटक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं है। वर्ष 2014-15 से सुपरन्यूमररी कोटे के तहत विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों के पाल्यों को लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम विश्वविद्यालय एक्ट तथा आर्डिनेंस की मूल भावना के खिलाफ है, कर्मचारियों और शिक्षकों को पाल्यों के मूल अधिकारों का हनन करता है और यह बेहद अन्यायपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण है। महाविद्यालयों के आधारिक सुविधाओं को टोटा हो गया है। संसाधनों एवं अनुदान के अभाव में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं पुरानी पड़ती जा रही हैं, खेल सुविधाएं कम होती जा रही हैं। और नये छात्रावासों की घोर आवश्यकता होने के बावजूद उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैंने नवम्बर, 2012 और फिर फरवरी, 2014 में विशेष महत्व के विषय के अंतर्गत यह मुद्दा इस सदन में उठाया था, परन्तु इस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से पुनः यह मांग करता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 संघटक महाविद्यालयों की समस्याओं को हल करने के लिए कुलपति को सख्त आदेश दिए जाएं।

---

*Not recorded.